

राजस्थान उच्च न्यायालय**जयपुर पीठ**

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11370/2021

मेसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 400/200 केवी, बस्सी,
दामोदपुरा, जयपुर, राजस्थान - 303301

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, (नोटिस को वित्त विभाग, प्रथम तल, मुख्य भवन, सरकारी सचिवालय, जयपुर-302005, राजस्थान के संयुक्त सचिव (कर) के माध्यम से दिया जाना है)
- भारत संघ, (नोटिस को सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से दिया जाना है)
- अग्रिम निर्णय के लिए राजस्थान प्राधिकरण (एएआर) माल और सेवा कर। एनसीआर भवन, स्टैच्यू सर्किल, सी-स्कीम जयपुर - 302005 (राजस्थान)

-----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री नरेंद्र सिंघवी के साथ
सुश्री प्रियंवदा जोशी

प्रतिवादीगण की ओर से : श्री किंशुक जैन के साथ
श्री सौरभ जैन

श्री जय लोढ़ा

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

निर्णय

आरक्षित: 09.07.2024

घोषित: .07.2024

अवनीश झिंगन, न्यायाधीश

1. यह याचिका माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत अग्रिम निर्णय के लिए राजस्थान प्राधिकरण (संक्षेप में 'एएआर') द्वारा पारित 31.05.2021 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत है और बिजली के पारेषण में लगा हुआ है। व्यवसाय के दौरान, याचिकाकर्ता ठेकेदारों को काम पर लगाता है। अनुबंध के निष्पादन के दौरान, सामग्री की आपूर्ति कार्यस्थल से की जाती है। ठेकेदार माल का परिवहन करता है और परिवहन के लिए चालान बनाता है। याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे पर एक अग्रिम निर्णय के लिए एक आवेदन दायर किया कि क्या मामले के तथ्यों में, अधिसूचना संख्या 12/2007 केंद्रीय कर (दर) (संक्षेप में 'अधिसूचना') की क्रम संख्या 18 के तहत माल का परिवहन छूट है। एएआर ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में 'सीजीएसटी अधिनियम') की धारा 97 के तहत आवेदन को अस्वीकार्य माना, क्योंकि याचिकाकर्ता आपूर्तिकर्ता नहीं था। इसलिए, यह वर्तमान याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि छूट अधिसूचना के लागू न होने की स्थिति में, याचिकाकर्ता रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, सेवाएं अधिसूचित श्रेणी में होने के कारण। उनका तर्क है कि धारा 95 और 97 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन केवल आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जा सकता है।

4. प्रतिवादी के विद्वान वकील इस पर आपत्ति करते हैं कि impugned आदेश अपील योग्य है। इसके विपरीत, अग्रिम निर्णय आपूर्तिकर्ता या प्रस्तावित आपूर्तिकर्ता द्वारा मांगा जा सकता है। उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता आपूर्तिकर्ता की परिभाषा के तहत नहीं आता है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, अपील सीजीएसटी अधिनियम की धारा 98(4) के तहत पारित आदेश के खिलाफ प्रदान की जाती है, न कि धारा 98(2) के तहत आदेश के खिलाफ।

6. इसमें शामिल मुद्दा है:-

"क्या माल या सेवाओं या दोनों का प्राप्तकर्ता रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, वह अग्रिम निर्णय मांग सकता है?"

7. सीजीएसटी अधिनियम का अध्याय XVII अग्रिम निर्णय से संबंधित है। परिभाषाएं धारा 95 में हैं और यह "जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो" से शुरू होती है।

खंड (क) के तहत 'अग्रिम निर्णय' प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण का एक निर्णय है, आवेदक के अनुरोध पर, धारा

97 की उप-धारा (2) या धारा 100 की उप-धारा (1) या धारा 101 सी में निर्दिष्ट मामलों या मुद्दों पर और माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में, जो आवेदक द्वारा किया जा रहा है या प्रस्तावित है।

खंड (ख) धारा 99 में संदर्भित अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण को परिभाषित करता है।

खंड (ग) के तहत 'आवेदक' को अधिनियम के तहत पंजीकृत या पंजीकरण प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

खंड (घ) के तहत आवेदन का मतलब धारा 97(1) के तहत प्राधिकरण को किया गया एक आवेदन है।

8. धारा 97(1) यह प्रावधान करती है कि अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन किसी भी आवेदक द्वारा दायर किया जा सकता है जो अग्रिम निर्णय प्राप्त करने की इच्छा रखता है। पूछे जाने वाले प्रश्न को बताते हुए एक आवेदन निर्धारित तरीके से किया जाना है और निर्धारित शुल्क के साथ होना चाहिए।

धारा 97(2) उन मुद्दों को निर्धारित करती है जिनके लिए अग्रिम निर्णय के लिए प्रश्न मांगा जा सकता है। उप-धारा 2 के खंड (ख) "इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना की प्रयोज्यता" वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक होगी।

9. धारा 98 अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन की प्राप्ति पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करती है। उप-धारा 2 के तहत, प्राधिकरण को आवेदन, रिकॉर्ड की जांच करने और आवेदक और संबंधित अधिकारी को सुनवाई का

अवसर प्रदान करने के बाद, आवेदन को या तो स्वीकार करने या अस्वीकार करने का आदेश पारित करना होगा। उप-धारा 2 का परंतुक यह प्रावधान करता है कि अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन उठाए गए प्रश्न पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो सीजीएसटी अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत आवेदक के मामले में लंबित या तय किया गया है। दूसरे परंतुक के अनुसार, सुनवाई का अवसर दिए बिना आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। तीसरा परंतुक आवेदन को अस्वीकार करने के लिए आदेश में कारणों को निर्दिष्ट करने का प्रावधान करता है। उप-धारा 3 आवेदक और संबंधित अधिकारी को उप-धारा 2 के तहत पारित आदेश की आपूर्ति करने के लिए बाध्य करती है। उप-धारा 4 के अनुसार, प्राधिकरण उसके सामने रखी गई सामग्री की जांच करने और सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, पूछे गए प्रश्नों पर अग्रिम निर्णय सुनाएगा। उप-धारा 5 उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसे अपनाया जाना है, यदि प्राधिकरण के सदस्यों के बीच राय का अंतर है। उप-धारा 6 प्राधिकरण को आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर अग्रिम निर्णय सुनाने के लिए बाध्य करती है। उप-धारा 7 निर्धारित करती है कि निर्णय सदस्यों द्वारा सुनाया और हस्ताक्षरित किया जाएगा और निर्धारित तरीके से प्रमाणित किया जाएगा।

10. रिवर्स चार्ज, आपूर्तिकर्ता और कर योग्य व्यक्ति की परिभाषाओं पर विचार करना उचित होगा। धारा 2(98) "रिवर्स चार्ज" को आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता की कर का भुगतान करने की देयता के रूप में परिभाषित करती है, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के तहत या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के तहत अधिसूचित माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की श्रेणियों के लिए।

धारा 2 (105) के अनुसार आपूर्तिकर्ता वह व्यक्ति है जो माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करता है और इसमें आपूर्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाला एजेंट भी शामिल होगा, जो माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में है।

धारा 2(107) 'कर योग्य व्यक्ति' को धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकृत या पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है।

11. बीस लाख से अधिक कारोबार वाले आपूर्तिकर्ता को धारा 22 के तहत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकरण प्राप्त करने के लिए बाध्य किया जाता है जहां से माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की जाती है, विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर। धारा 22 में निहित कुछ भी होने के बावजूद, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 24 में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। धारा 24 के खंड (iii) के तहत, रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

12. याचिकाकर्ता, यदि अधिसूचना द्वारा छूट नहीं दी गई है, तो रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरे शब्दों में, प्राप्तकर्ता होने के बावजूद कर का भुगतान करने की देयता याचिकाकर्ता की है। याचिकाकर्ता को आवेदन करने से बाहर करने के लिए 'अग्रिम निर्णय' की परिभाषा पर भरोसा किया गया, इस पृष्ठभूमि में विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होने के कारण याचिकाकर्ता कर योग्य व्यक्ति की परिभाषा के तहत आएगा।

13. अधिनियम के तहत एक पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकरण प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति धारा 95 में 'आवेदक' के दायरे में आता है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 24 के तहत, रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होने के कारण याचिकाकर्ता के लिए पंजीकृत होना अनिवार्य है।

14. एएआर द्वारा 'अग्रिम निर्णय' की परिभाषा की व्याख्या में एक त्रुटि है। अग्रिम निर्णय की परिभाषा नीचे उद्धृत है:-

"95 (क) "अग्रिम निर्णय" का अर्थ प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण (या राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण) द्वारा एक आवेदक को धारा 97 की उप-धारा (2) या धारा 100 की उप-धारा (1) (या धारा 101सी) में निर्दिष्ट मामलों या प्रश्नों पर, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में, जो आवेदक द्वारा किया जा रहा है या प्रस्तावित है, प्रदान किया गया एक निर्णय है।"

माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में परिभाषा का उत्तरार्द्ध भाग जो आवेदक द्वारा किया जा रहा है या प्रस्तावित है, आवेदक की परिभाषा के दायरे को प्रतिबंधित नहीं करता है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता है।

15. इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि धारा 95 "इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो" से शुरू होती है, जिससे परिभाषित शब्द को उस संदर्भ में एक व्याख्या देने की गुंजाइश मिलती है जिसमें इसका उपयोग किया जा रहा है।

16. वैनगार्ड फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मद्रास बनाम फ्रेजर एंड रॉस और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, एआईआर 1960 एससी 971 में रिपोर्ट किया गया, निम्नानुसार आयोजित किया:-

"इस तर्क का मुख्य आधार अधिनियम की धारा 2(9) में "बीमाकर्ता" शब्द की परिभाषा है। यह बताया गया है कि परिभाषा "बीमाकर्ता का मतलब है" शब्दों से शुरू होती है और इसलिए व्यापक है। यह स्वीकार किया जा सकता है कि आम तौर पर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "बीमाकर्ता" शब्द को एक व्यक्ति या कॉर्पोरेट निकाय आदि के रूप में परिभाषित किया गया है जो वास्तव में बीमा के व्यवसाय को चला रहा है, यानी किसी भी प्रकार के बीमा के अनुबंधों को प्रभावित करने का व्यवसाय। लेकिन धारा 2 "इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो" शब्दों से शुरू होती है और फिर विभिन्न परिभाषा खंड आते हैं जिनमें से (9) एक है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सभी सांविधिक परिभाषाओं या संक्षिप्ताक्षरों को उन परिभाषा खंडों में विभिन्न रूप से व्यक्त की गई योग्यता के अधीन पढ़ा जाना चाहिए जिन्होंने उन्हें बनाया है और यह हो सकता है कि जहां परिभाषा व्यापक है, वहां भी परिभाषित शब्द को एक निश्चित चीज का मतलब कहा जाता है, यह संभव है कि शब्द का अधिनियम के विभिन्न खंडों में विषय या संदर्भ के आधार पर कुछ अलग अर्थ हो। यही कारण है कि विधियों में सभी परिभाषाएं आम तौर पर वर्तमान मामले में उपयोग किए गए शब्दों के समान शब्दों के साथ शुरू होती हैं, अर्थात्, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो। इसलिए अधिनियम के विभिन्न खंडों में "बीमाकर्ता" शब्द का अर्थ खोजने में, इसे आमतौर पर दिया जाने वाला अर्थ वह है जो परिभाषा खंड में दिया गया है। लेकिन यह अपरिवर्तनशील नहीं है और अधिनियम में ऐसे खंड हो सकते हैं जहां शब्द का अर्थ उस विषय या संदर्भ के कारण बदल सकता है जिसमें शब्द का उपयोग किया गया है और वह परिभाषा खंड में शुरूआती वाक्य को प्रभावित करेगा, अर्थात्, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो। इस योग्यता के मद्देनजर, न्यायालय को न केवल शब्दों को देखना होगा बल्कि संदर्भ, सहयोग और

ऐसे शब्दों के उद्देश्य को भी देखना होगा जो ऐसे मामले से संबंधित हैं और परिस्थितियों में शब्दों के उपयोग द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अर्थ की व्याख्या करनी होगी। इसलिए, हालांकि आम तौर पर अधिनियम में उपयोग किए गए "बीमाकर्ता" शब्द का अर्थ एक व्यक्ति या कॉर्पोरेट निकाय होगा जो वास्तव में बीमा के व्यवसाय को चला रहा है, यह हो सकता है कि कुछ खंडों में शब्द का कुछ अलग अर्थ हो।"

(जोर दिया गया)

17. इस मामले पर एक और दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(3) के तहत, परिषद की सिफारिश पर सरकार रिवर्स चार्ज आधार पर कर के भुगतान के लिए माल या सेवाओं या दोनों की श्रेणियों को अधिसूचित करती है। यह निर्धारित किया गया है कि अधिनियम के सभी प्रावधान माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे, जिसे कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति माना जाएगा। रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्राप्तकर्ता को कर के भुगतान के उद्देश्य के लिए आपूर्तिकर्ता का एक कल्पना दिया गया है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(3) के तहत कल्पना को अग्रिम निर्णय मांगने के लिए अध्याय XVII के दायरे में रिवर्स चार्ज पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यापारी को लाकर पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। कर प्रभार के आधार पर अग्रिम निर्णय (Advance Ruling) प्राप्त करने के लिए अध्याय XVII के दायरे में आता है।

18. प्रतिवादी की वैकल्पिक उपाय की आपत्ति पर विचार करना उचित होगा। अग्रिम निर्णय के खिलाफ अपील सीजीएसटी अधिनियम की धारा 100 के तहत प्रदान की गई है। संबंधित अधिकारी, अधिकार क्षेत्र के अधिकारी या आवेदक धारा 98(4) के तहत दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 98(2) के तहत

आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ कोई अपील प्रदान नहीं की गई है। याचिकाकर्ता का आवेदन धारा 98(2) के तहत ही, अमान्य होने के कारण प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया गया था। धारा स्पष्ट है कि अपील केवल सीजीएसटी अधिनियम की धारा 98(4) के तहत सुनाए गए आदेशों के खिलाफ दायर की जा सकती है।

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। मामले को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 98(4) के तहत आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए एएआर (AAR) को वापस भेजा जाता है।

20. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

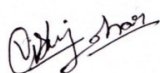
(आशुतोष कुमार), न्यायाधीश

(अवनीश झिंगन), न्यायाधीश

चंदन/रिया /

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़